पूरी बेंच

माननीय एस.एस. संधावालिया सी.जे., एस.एस. कांग और जी.सी. मितल,

जे.जे. के समक्ष

भारत संघ, - अपीलकर्ता,

बनाम

गिरधारी और अन्य, - प्रतिवादी।

1980 के एफ.ए.ओ. संख्या 466 में क्रॉस ऑब्जेक्शन नंबर 36-सी-II 1981।

8 जनवरी 1982.

पंजाब अधिग्रहण और अचल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम (1953 का पंजाब अधिनियम II) - धारा 11 - 1870 का न्यायालय शुल्क अधिनियम 7 - धारा 8 और अनुसूची I, अनुच्छेद 1 - धारा 11 के तहत अपील का ज्ञापन - उस पर देय न्यायालय शुल्क - क्या होना चाहिए यथामूल्य या नहीं.

माना गया कि पंजाब अधिग्रहण और अचल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1953 की धारा 11 के तहत अपील के ज्ञापन पर देय अदालती फीस अदालत फीस अधिनियम 1870 के अनुच्छेद 1 की अनुसूची 1 के साथ पढ़ी गई धारा 8 के अनुसार यथामूल्य होनी चाहिए।

(अनुच्छेद16)

कंवर जगत बहादुर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1957

पंजाब 32.

भारत संघ बनाम विरसा सिंह, 1979 पी.एल.आर. 340.

कंवलजीत सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। 1979 की एफ.ए.ओ. संख्या 269, 3 सितंबर 1979 को निर्णय लिया गया। खारिज कर दिया गया।

आदेश 41, नियम 22 सीपीसी के तहत क्रॉस आपत्तियां प्रार्थना करती हैं कि इन क्रॉस-आपत्तियों को स्वीकार किया जाए, दावेदार प्रतिवादी की अधिग्रहित भूमि और पेड़ों के संबंध में मुआवजा दिया जाए। कृपया 25 मई 1964 से विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए मुआवज़े के अतिरिक्त 15 प्रतिशत की दर से 23,450 रुपये की अतिरिक्त राशि और 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी बढ़ाया जाए। बढ़ी हुई मुआवज़े की राशि पर कृपया अनुमति दी जाए. इन प्रति आपत्तियों की लागत भी प्रदान की जा सकती है।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता एच.एस. बराड़।

एम. एस. बेदी, वकील, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.:

(1) क्या पंजाब अधिग्रहण और अचल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1953 की धारा 11 के तहत अपील के ज्ञापन पर देय अदालती फीस अदालत फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची I और अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ी गई धारा 8 के अनुसार यथामूल्य होनी चाहिए, या उक्त अधिनियम की अनुसूची II, अनुच्छेद II के तहत एक निश्चित प्रश्न है - यह मुख्य कानूनी प्रश्न है जो इस पूर्ण पीठ के समक्ष निर्धारण के लिए आता है। अधिक स्पष्ट मुद्दा कंवर जगत बहादुर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1) में डिवीजन बेंच के फैसले (इस संदर्भ में) की शुद्धता है।

(2) प्रश्न की पूरी तरह से कानूनी प्रकृति को देखते हुए, तथ्यों पर ध्यान देना वास्तव में अनावश्यक और बेकार है। यह कहना पर्याप्त है कि पंजाब अधिग्रहण और अचल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1953 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 11 के तहत अपील के ज्ञापन पर देय अदालती शुल्क के संबंध में न्यायिक राय में विसंगति है। कंवलजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय की दो एकल पीठ के फैसले में। (2), महा सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, गुड़गांव के माध्यम से मध्यस्थ के रूप में (3)। इसलिए इस मुद्दे को 1981 के

एफ.ए.ओ. संख्या 466 (भारत संघ बनाम गिरधारी लाई) में 1981 की क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या 36 पर देय न्यायालय शुल्क के संबंध में स्पष्ट रूप से उठाया गया है। और मामले को आधिकारिक निर्णय के लिए इस पूर्ण पीठ के समक्ष रखा गया है।

(3) मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार के लिए मिसाल के सिद्धांत का सख्त अनुशासन इस संदर्भ में विवाद की गॉर्डियन गाँठ को साफ़ कर देता है। यह मुद्दा अब अंतिम न्यायालय की बाध्यकारी मिसाल से तय हो गया है। यह पहले सिद्धांतों और यहां तक कि क़ानून की भाषा पर किसी भी विचार को टाल देता है क्योंकि मेरा मानना है कि शहदू गंगाराम भागडे बनाम विशेष कर्तव्य नियंत्रक, अहमदाबाद और अन्य (4) का अनुपात अब इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से नियंत्रित करता है। और इसलिए यह इंगित करना पर्याप्त है कि यह वर्तमान मामले में भी स्पष्ट रूप से और अपरिहार्य रूप से कैसे लागू होता है।

(4) कंवर जगत बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले की शुरुआत में ही विज्ञापन देना उचित है, जो अभी भी इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उसमें, हमारे सामने समान प्रश्न विचार के लिए आया था। इस दृष्टिकोण को अपनाने में डिवीजन बेंच मुख्य रूप से निम्नलिखित चार आधारों से प्रभावित थी:

(i) कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 8 चार्जिंग धारा नहीं थी, और वास्तव में चार्जिंग प्रावधान उसकी अनुसूची-I और II थे, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूची II, अनुच्छेद 11 इस मुद्दे को नियंत्रित करेगा;

(ii) कि अधिनियम के तहत मध्यस्थ का पुरस्कार डिक्री या डिक्री के बल वाला आदेश नहीं है, मामला न्यायालय-फीस अधिनियम की अनुसूची II, अनुच्छेद 11 की भाषा में आएगा;

(iii) प्राथमिक निर्भरता हीराजी विरजी जंगबारी बनाम बॉम्बे सरकार में एकल पीठ के फैसले पर रखी गई थी, (5) और उसमें दिए गए दृष्टिकोण का बिना शर्त पालन किया गया था, और

(iv) डिवीजन बेंच ने आनंद लाई चक्रवर्ती और अन्य के मामले में

रैंकिन, सी.जे. के विपरीत दृष्टिकोण से असहमति जताई। (6) और देबी दीन बनाम राज्य सचिव, (7) में।

(5) यह कि पूर्वोक्त परिसर अब शाहदु गंगाराम भागडे के मामले (सुप्रा) द्वारा पूरी तरह से पलट दिया गया है, इस प्रकार कंवर जगत बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) में अनुपात की आधारशिला टूट गई है, यह मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है। इसकी सराहना करने के लिए, किसी को बॉम्बे कोर्ट-फीस अधिनियम, 1959 की धारा 7 (1) के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा जो बॉम्बे उच्च न्यायालय में व्याख्या के लिए गिर गए थे। और बाद में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य के समक्ष भी, और कोर्ट-फीस अधिनियम, 1870 की धारा 8 के नियम समान स्थिति में हैं और इसलिए, उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना उपयुक्त है: -

सेक. न्यायालय-फीस अधिनियम, 1870 के 8

"सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए वर्तमान में लागू किसी भी अधिनियम के तहत मुआवजे से संबंधित आदेश के खिलाफ अपील के ज्ञापन पर इस अधिनियम के तहत देय शुल्क की राशि। इसकी गणना पुरस्कार की राशि और अपीलकर्ता द्वारा दावा की गई राशि के बीच अंतर के अनुसार की जाएगी।

सेक. बॉम्बे कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7(1).

"सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए वर्तमान में लागू किसी भी अधिनियम के तहत मुआवजे से संबंधित आदेश के खिलाफ अपील के ज्ञापन पर इस अधिनियम के तहत देय शुल्क की राशि। इसकी गणना प्रदान की गई राशि और अपीलकर्ता द्वारा दावा की गई राशि के बीच अंतर के अनुसार की जाएगी।

6. उपरोक्त दोनों प्रावधानों की पहचान पर ध्यान देने के बाद, यह उजागर करना आवश्यक है कि वही मुद्दा अब हमारे सामने एक डिवीजन बेंच

के समक्ष विचार के लिए आया है। बॉम्बे कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में चतुस्शाखिया ब्रह्मारिंदा गयाराम ट्रस्ट बनाम भारत संघ (8) के मामले में। फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि बेंच के सामने महत्वपूर्ण सवाल हीराजी वीरजी जंगबारी के मामले (सुप्रा) में बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले के दृष्टिकोण की शुद्धता का था। एक विस्तृत फैसले में, जिस पर अब अंतिम न्यायालय की मंजूरी की मुहर लग गई है, डिवीजन बेंच ने आनंद लाई चक्रवर्ती और अन्य मामले (सुप्रा) में रैंकिन, सीजे द्वारा बताए गए अनुपात को बड़े पैमाने पर उद्धृत करने के बाद प्राथमिकता दी। उन्होंने विशेष रूप से कंवर जगत बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया, और एक विश्लेषण में जो इसके विवरण में उल्लेखनीय है, उन्होंने उससे असहमति व्यक्त की। नतीजतन, हीराजी वीरजी जंगबारी के मामले (सुप्रा) में पहले के बॉम्बे दृष्टिकोण को खारिज कर दिया गया था और यह माना गया था कि मुआवजा पुरस्कार के खिलाफ अपील के ज्ञापन पर देय अदालती शुल्क यथामूल्य होगा। बॉम्बे कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 7 (1) के अनुसार, उसकी अनुसूची । अनुच्छेद 3 के साथ पढ़ें।

7. अब इस मामले को समाप्त करने वाली बात यह है कि शहादु गंगाराम भागडे के मामले (सुप्रा) में अंतिम न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न फिर से बॉम्बे कोर्ट-फीस अधिनियम के संदर्भ में उठाया गया था। जाहिरा तौर पर, जिन तर्कों को पहले कंवर जगत बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) में समर्थन मिला था, उन्हें उनके आधिपत्य के समक्ष भी उठाया गया था, लेकिन उनके हाथों उन्हें संक्षेप में अस्वीकार कर दिया गया था। जहां तक इस रुख का संबंध है कि कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 8 चार्जिंग धारा नहीं है और इसलिए, अनुसूची II, अनुच्छेद 11 लागू होगी, उनके आधिपत्य ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ इसे निर्णायक रूप से खारिज कर दिया: -

“यह प्रावधान कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा 8 के समान है। यह अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर अपील पर स्पष्ट रूप से लागू होता है। यह सच है कि यह प्रावधान कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह केवल देय न्यायालय शुल्क की गणना का प्रावधान करता है। लेकिन वह प्रावधान यह स्पष्ट

करता है कि यह यथामूल्य आधार पर देय न्यायालय शुल्क की गणना से संबंधित है। इसका निश्चित न्यायालय शुल्क के भुगतान का प्रावधान करने वाले किसी भी अनुच्छेद से कोई संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए, उस प्रावधान के तहत प्रदान की गई गणना केवल अनुसूची 1 में एक या अन्य लेखों के तहत देय न्यायालय शुल्क की हो सकती है"

8. इसी तरह इस विवाद से निपटते हुए कि अधिनियम के तहत मध्यस्थ का पुरस्कार एक डिक्री या डिक्री के बल वाला आदेश नहीं है और इसलिए, मामला बॉम्बे कोर्टफीसएक्ट की धारा 7 (1) के दायरे से बाहर होगा। . और उसकी अनुसूची II के अंतर्गत आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने इसे निम्नलिखित शर्तों में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया: -

"हमें इस तर्क में कोई बल नहीं दिखता कि बॉम्बे कोर्ट-फीस अधिनियम, 1959 की धारा 7 (1) के तहत अपील की जा सकती है, अपील के तहत आदेश में डिक्री का बल होना चाहिए। वह अनुभाग ऐसा नहीं कहता. इसलिए, हमारे लिए शब्दों को जोड़ना उचित नहीं होगा; धारा 7(1) में 'आदेश' शब्द के बाद "डिक्री का बल होना"। वास्तव में यह अनुभाग इतना सरल है कि इसकी किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। उस दृष्टि से, हमारे लिए बॉम्बे कोर्ट-फीस अधिनियम, 1959 की अनुसूची II के किसी भी अनुच्छेद पर विचार करना आवश्यक नहीं है। हमें बस यह देखना है कि अनुसूची I के किस अनुच्छेद के तहत, कोर्ट-फीस देय है..."

9. फिर आनंद लाई चक्रवर्ती और अन्य में रैंकिन, सी.जे. के पहले के दृश्य का विज्ञापन। पुन: मामला (सुप्रा), उनके आधिपत्य, वहां से उद्धृत शब्दों में, और उसमें स्पष्ट रूप से स्वीकृत कथन।

10. अंत में, उनके आधिपत्य ने, हीराजी वीरजी जंगबारी के मामले (सुप्रा) में पहले के दृष्टिकोण को निम्नलिखित निष्कर्ष टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया:-

"उपर्युक्त कारणों से, हम सोचते हैं कि चतुस्शाखिया ब्रहमवृंदा गयारन ट्रस्ट

बनाम भारत संघ, (9) में उच्च न्यायालय का निर्णय सही है। इस दृष्टि से, हमारे लिए कंवर जगत बहादुर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (10) में पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय की सत्यता पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

11. उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि सभी चार परिसर जिन पर कंवर जगत बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) का अनुपात निर्भर था, अब आधिकारिक रूप से ध्वस्त कर दिए गए हैं। उसमें स्वीकार की गई दलीलों को सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है और हीराजी विरजी जंगबारी के मामले (सुप्रा) में निर्णय, जो इसका मुख्य आधार था, अब खारिज कर दिया गया है। आनंद लाई चक्रवर्ती और अन्य पुन: मामला (सुप्रा) जिस पर स्पष्ट रूप से असहमति व्यक्त की गई थी, अब अंतिम न्यायालय द्वारा बिना किसी अनिश्चित शर्तों के फिर से पुष्टि की गई है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कंवर जगत बहादुर सिंह का मामला (सुप्रा), शहादु गंगाराम भागडे के मामले (सुप्रा) में कानून की स्पष्ट और आधिकारिक व्याख्या को देखते हुए अब मैदान में नहीं रह सकता है।

12. मैं समान रूप से एक आधे-अधूरे मन से दिए गए तर्क का निपटारा करना चाहूंगा कि कंवर जगत बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) को, उसके उद्धरण (शहादु गंगाराम भागाडेकेस में पैराग्राफ 10) के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया गया है।) यह रेखांकित करने योग्य है कि चतुर्शाखिया ब्रह्मवृंदा गयारन ट्रस्ट के मामले (सुप्रा) में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंवर जगत बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) से विस्तार से असहमति व्यक्त की थी और विशेष रूप से पूर्व को मंजूरी देते हुए, उनके आधिपत्य आवश्यक रूप से अनुपात को अस्वीकार कर देंगे। बाद वाला मामला. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़े पैमाने पर पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि कंवर जगत बहादुर सिंह का मामला (सुप्रा), अब अच्छा कानून नहीं है। उनके आधिपत्य द्वारा की गई अंतिम टिप्पणियों पर एकमात्र निर्माण संभव है कि कानून को इसके विपरीत तय करने और घोषित करने के बाद, उन्होंने कंवर

जगत बहादुर, सिंह के मामले सहित अन्य निर्णयों पर व्यक्तिगत रूप से विचार करना और उन्हें खारिज करना आवश्यक नहीं समझा)।

13. अब अंतिम न्यायालय की बाध्यकारी मिसाल के अलावा, बॉम्बे कोर्ट फीस अधिनियम के संदर्भ में, ऐसा प्रतीत होता है कि; 1870 के कोर्ट-फीस अधिनियम के तहत मिसाल का महत्व दूसरी तरफ भी समान रूप से है। यह हमारे सामने स्वीकार किया गया मामला था कि बॉम्बे और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों ने कंवर जगत बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) में दृष्टिकोण से अपनी असहमति व्यक्त की है। कलकत्ता, इलाहाबाद और यहां तक कि हमारे पूर्ववर्ती लाहौर उच्च न्यायालय ने पूरन चंद और अन्य बनाम सम्राट और अन्य (11) मामले में लगातार विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। प्रतिवादी के विद्वान वकील, दबाव डालने के बावजूद, किसी भी निर्णय का हवाला देने में असमर्थ थे जो अभी भी कंवर जगत बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) के अनुरूप है।

14. निष्कर्ष निकालने के लिए, अब यह माना जाना चाहिए कि कंवर जगत बहादुर सिंह का मामला (सुप्रा), अब अच्छा कानून नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है।

15. उपरोक्त के आवश्यक परिणाम के रूप में, यह होगा कि इस न्यायालय के बाद के सभी एकल पीठ के फैसले, कंवर जगत बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) के अनुरूप विचार करते हुए, गलती से तय किए गए हैं। इसलिए, हम भारत संघ बनाम विरसा सिंह, (12) और कंवलजीत सिंह और अन्य को खारिज कर देंगे। बनाम पंजाब राज्य और अन्य (13)।

16. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, प्रारंभ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस आशय का दिया गया है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत अपील के ज्ञापन पर देय न्यायालय शुल्क यथामूल्य होना चाहिए। न्यायालय-फीस अधिनियम, 1870 की अनुसूची-1 अनुच्छेद 1 के साथ पठित धारा 8 के अनुसार।

17. इस न्यायालय में मिसाल की लगातार धारा को ध्यान में रखते हुए, जिसे हमने अब उलट दिया है, स्पष्ट रूप से प्रति-आक्षेपकर्ता को अदालत-शुल्क में कमी को पूरा करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। हम तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दो महीने की अवधि की अनुमति देते हैं।

(1) ए.आई.आर. 1957 पी.बी. 32.
(2) 1979 के एफ.ए.ओ. 269 का निर्णय 3 सितम्बर 1979 को हुआ।
(3) एफ.ए.ओ. 185/80 का निर्णय 15 दिसम्बर 1980 को हुआ।
(4) ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 1887.
(5) ए.आई.आर. 1945 बम्बई 348.
(6) ए.आई.आर. 1932 कलकत्ता 346.
(7) ए.आई.आर. 1939 इलाहाबाद 127
(8) (1968) एलएक्सएक्स बॉम्बे लॉ रिपोर्टर 407।
(9) (1968) 70 बम। एल. आर. 407.
(10) आई.एल.आर. (1957) पी.बी. 142 (ए.आई.आर.1957 पृ. 32)
(11) ए.आई.आर. 1926 लाहौर 343.
(12) 1979 पी.एल.आर. 340.
(13) एफ.ए.ओ. 269/79 निर्णय 3 सितम्बर 1979 को।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy